मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2018-20 /R.N.I. No. 66400/97

अवैध बिल्डिंगों की सूची नगर निगम के पास नहीं 3
सीएम घोषणा के सारे विकास कार्यों पर रोक 4
दिलजीत दोसांझ के साथ खड़े हुए पंजाबी गायक 5
किसान राजनीति के दो बदनुमा दाग 6
अवैध फार्महाउसों को कब तक दिए जाते रहेंगे नोटिस 8

वर्ष 34 | अंक 4 | फरीदाबाद | 6-12 दिसम्बर 2020 | फोन-8851091460 | ₹3.00

कॉरपोरेट दलाल मोदी सरकार से किसान न उगलते बन रहे न निगलते बन रहे

दो दौर की बातचीत नाकाम, कितने दौर और होंगे ?

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद : किसानों ने केन्द्र की मोदी सरकार को फँसा दिया है। एकतरफ़ उस पर किसानों का दबाव है तो दूसरी तरफ वो मुट्ठी भर पूँजीपति हैं जिनके चंदे से उनकी सरकार बनी है। पहली बार किसानों का मुद्दा सारी राजनीति के केन्द्र में है। इस समय राजधानी दिल्ली को किसानों ने तीन तरफ से घेर रखा है लेकिन असली मोर्चा सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर लगा हुआ है। सोनीपत, गाजियाबाद, नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर किसान बैठे हैं और भारी जाम लगा हुआ है। इसी तरह फरीदाबाद की और से होडल एवं बल्लभगढ़ के किसानों के आने की सूचना पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अभी तक मोदी सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच दो दौर की बेनतीजा बातचीत हो चुकी है। तीसरे दौर की बातचीत 5 दिसम्बर को होगी।

दो दौर की बातचीत में मोदी सरकार पूँजीपतियों का पक्ष लेती नज़र आई। सरकार के रवैये से लगता है कि किसानों के खिलाफ साज़िश पिछले साल से ही शुरू हो गई थी। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भारी जीत के साथ लौटते ही मोदी ने तीनों कृषि बिलों

का ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दे दिया था। उधर पूँजीपतियों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। अब यह जानकारी सामने आ रही है कि अंबानी और अडानी ने देश के कई हिस्सों में स्टोरेज आदि की व्यवस्था करने में काफ़ी पैसा झोंका है। रेलवे से मालगाड़ी के लिए क़रार किया गया है। पाठकों को याद होगा कि ऐसी ही अडानी की ट्रेन को संगरूर में किसानों ने रोक दिया था।

सरकार से बातचीत में हिस्सा लेने वाले सिरसा के किसान नेता बलदेव सिंह का कहना है कि हमने सरकार को उनके तीनों क़ानूनों की कमियां बताईं, उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि कमियां हैं और वे संशोधन करेंगे। हमने कहा कि हम संशोधन नहीं चाहते हैं कानूनों को वापस चाहते हैं। हमने यह भी मांग की है कि एमएसपी को निश्चित और कानून के तहत लागू किया जाना चाहिए।

पर, लगता है ऐसा होगा नहीं। मोदी सरकार को अगर तीनों क़ानूनों में संशोधन करना होता तो वह बहुत पहले ही इसकी घोषणा कर देती लेकिन क्रोनी कैपिटिलिस्ट उसे ऐसा करने नहीं देंगे।

बहरहाल, पंजाब के किसान लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आये हैं। उनमें गजब का आत्मविश्वास है। वे केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलने गये तो अपना नाश्ता पानी साथ ले गये और सरकार का माल खाने से मना कर दिया। बॉर्डर पर तली जा रही पूड़ी और जलेबी ने सरकार को चकरघिन्नी बना दिया है।

हरियाणा को मिला सबक़

पंजाब के किसानों ने आंदोलन की पहल की है। लेकिन हरियाणा के किसानों ने सितम्बर में ही काले क़ानूनों के ख़िलाफ़ कुरुक्षेत्र में पहला प्रदर्शन किया और खट्टर सरकार की लाठियाँ खाईं। यह आंदोलन भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) ने किया था। व्यापक राजनीतिक और सामाजिक समर्थन नहीं मिलने से इसके नेता चुप होकर बैठ गए।

अब पंजाब के किसानों को सड़कों पर देखकर हरियाणा के किसान भी जाग उठे हैं। तमाम खाप पंचायतें अब अपनी गलती मान रही हैं और वे अब इस आंदोलन में शामिल होने को तैयार हो गए हैं।

हरियाणा में कांग्रेस कमजोर विपक्ष की भूमिका में है। जन नायक जनता पार्टी (जेजेपी) जो किसानों का वोट लेकर सत्ता तक पहुँची, अब उन्हें ही भूल गई। अब जब हरियाणा में किसानों ने पंचायतें शुरू कर दी हैं तो दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला को होश आना शुरू हुआ है। जो पंजाब के बादल परिवार को बहुत पहले आ चुका था। दोनों पिता पुत्र अब कह रहे हैं कि अगर एमएसपी के मामले में किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो दुष्यंत सरकार से बाहर आ जाएगा। हालाँकि सत्ता के नशे में डूबी जेजेपी शायद ही ऐसा कर पाये।

जेजेपी ही नहीं खट्टर सरकार भी घोर संकट में घिर गई है। सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय प्रत्याशी सोमबीर सांगवान ने न सिर्फ अपना समर्थन वापस ले लिया बल्कि लाइवस्टाक बोर्ड की चैयरमैनी भी छोड़ दी। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो निर्दलीय विधायक सरकार से गले मिलने को ललकते हों उनमें से कोई समर्थन वापस ले ले तो खट्टर सरकार की विश्वसनीयता फ़िलहाल ख़तरे में तो पड़ ही गई है। हरियाणा के किसानों के सड़कों पर निकलने की देर भर है।

खट्टर ने रबी ख़रीद की समीक्षा की

हरियाणा सरकार 1975 प्रति क्विंटल के एमएसपी से गेहूं, 4650 प्रति क्विंटल एमएसपी दर से सरसों, 5100 एमएसपी दर से चना और 5885 एमएसपी से सूरजमुखी की खरीद करेगी। राज्य में गेहूं की खरीद के लिए 389 मंडियां स्थापित की जाएंगी। सीएम ने रबी खरीद सीजन 2021-22 की समीक्षा की।

एक साल पहले से टूटी सड़कें मंत्री मूलचंद को अब नज़र आईं... सड़क निर्माण फंड का बड़ा हिस्सा अफसर ऊपर ही डकार लेते हैं

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर की कहीं न कहीं सड़कें तो हमेशा ही टूटी रहती हैं, ऐसा कभी देखने में नहीं आया जब शहर की तमाम सड़कों को चकाचक कहा जा सके। एक सड़क बन कर तैयार होती है तब तक दो टूट चुकी होती हैं और जब तक उनके बनने का नम्बर आता है तब तक और चार टूट चुकी होती हैं। लेकिन बीते एक साल तो सड़कों के टूटने पर 'विशेष कृपा' रही है।

स्थानीय विधायक एवं राज्य के परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा, जो रोज़ाना यहीं घूमते रहते हैं, उनको ये टूटी सड़कें केवल गत सप्ताह ही नज़र आई, वह भी तब, जब वे सड़कों का निरीक्षण करने निकले। है न कमाल की बात। लगता है उनको टूटी सड़कों का निरीक्षण करने की जरूरत तब महसूस हुई जब कुछ सड़कों की मुरम्मत के लिये थोड़े-बहुत फंड का जुगाड़ नगर निगम या 'हूडा' के पास हो गया होगा, ताकि मुरम्मत शुरू होने के वक्त वे नारियल फ़ोड़ते वक्त कह सकें कि निरीक्षण करने के तुरन्त बाद उन्होंने प्रयास किये तो काम शुरू हो गया।

एनआईटी के औद्योगिक क्षेत्र में तो ऐसे गड्ढेदार कच्चे रास्ते बन गये है जहां पहले कभी पक्की सड़क हुआ करती थी।

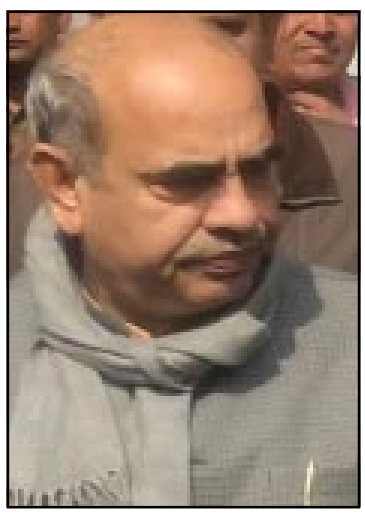

इन रास्तों को अब टूटी सड़क कहना भी बेमानी लगता है क्योंकि वहां अब ऐसा कोई चिन्ह बकाया नहीं है जिसे देखकर कहा जा सके कि यहां कभी सड़क बनी भी थी जबकि नगर निगम व पुराने कॉम्प्लेक्स प्रशासन खाते से यहां बीसियों बार सड़कें बन चुकी हैं। गौरतलब है कि यह कोई वीरान इलाका नहीं यहां सड़क के दोनों और 50-60 साल पुरानी फैक्ट्रियां चल रही हैं जिनमें हज़ारों श्रमिक व अन्य लोग सारा दिन आते-जाते रहते हैं। इन फैक्ट्रियों को कच्चा माल देने व तैयार माल ले जाने के लिये बड़े-बड़े ट्रक व ट्राले भी गड्ढों में डोलते-झूलते हुए यहां आते-जाते हैं। धूल इतनी भयंकर उड़ती है कि रास्ता भी ढंग से नहीं दिख पाता।

पॉश कहे जाने वाले सेक्टरों की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। सेक्टर आठ व सात के कोने पर स्थित मंत्री जी के कार्यालय के सामने सजावट के लिये पुलिस तो जरूर तैनात रहती है परन्तु वहां टूटी सड़क व हर वक्त खड़ी रहने वाली गाड़ियों से जाम लगा रहता है; इसका निरीक्षण मंत्री जी कब करेंगे? तमाम सेक्टरों की सड़कों में छोटे-बड़े गड्ढे मौजूद हैं जिनसे बचने के लिये जब वाहन इधर-उधर होते हैं या ब्रेक मारते हैं तो दुर्घटनायें भी होती रहती हैं जिनका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। बीपीटीपी चौक से सेक्टर 12-14 के बीच से होकर मथुरा रोड तक जाने वाली सड़क की जो मुरम्मत की है वह भी देखने वाली है; लगता है जैसे किसी ने रोते-पीटते सिर से बला टालने का प्रयास किया है, कहीं गड्ढे भर दिये तो कहीं छोड़ दिये गये। स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर भर की जो सड़कें खोद डाली हैं, वहां जिस लापरवाही से काम के नाम पर तमाशा बनाया हुआ है वह भी देखने वाला है। ऐसे

शेष पेज दो पर

एमसीएफ ने बैंक पर लगाया ताला, ये किस अफसर का है खेल

सौ रूपये लीज पर दी थी जगह, अब एक करोड़ की देनदारी निकाली

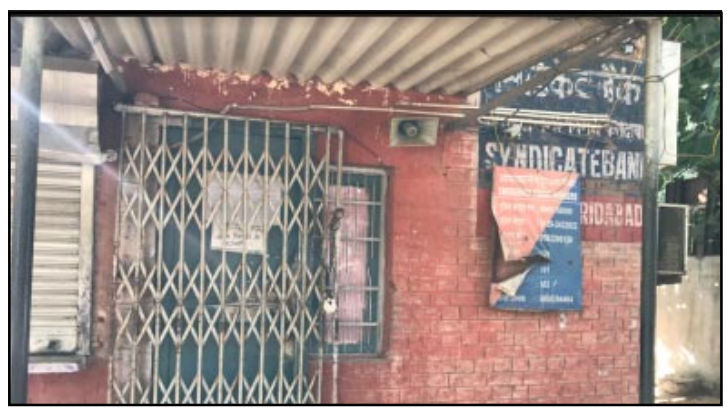

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद : नगर निगम फ़रीदाबाद (एमसीएफ) के कैंपस में चलने वाले सिंडिकेट बैंक (अब केनरा बैंक) पर नगर निगम ने ताला लगा दिया है। नगर निगम ने यह कार्रवाई प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने और अन्य मदों के बकाया होने पर की है। इस कार्रवाई से सबसे ज़्यादा परेशान एमसीएफ के कर्मचारी हैं, क्योंकि उनको वेतन लेने से लेकर पैसा निकालने और अन्य छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए इसी ब्रांच में जाना पड़ता है।

शेष पेज दो पर